

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य राजस्व आयुक्त,
उत्तराखण्ड देहरादून।

राजस्व विभाग

देहरादून: दिनांक: 20 अगस्त, 2008

विषय:- मुख्य राजस्व आयुक्त कार्यालय, उत्तराखण्ड के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु
धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1470/VIII-2/2007.08 दिनांक 1 फरवरी, 2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य राजस्व आयुक्त कार्यालय, उत्तराखण्ड के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या 1712/राजस्व/2003 दिनांक 24 जनवरी, 2004 द्वारा 50.00लाख की धनराशि स्वीकृति की गयी थी उन्हें शासनादेश संख्या 22(1)/18(1)/2007 दिनांक 6 मार्च 2007 द्वारा रु0 174.65 के आगणन पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। पुनः उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित आगणन रु0 276.27 लाख का टी0ए0सी द्वारा परीक्षणोपरान्त रु0 255.92 लाख के आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-09 में रु0 205.92 लाख की धनराशि को व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- उपरोक्त धनराशि व्यय करते समय मितव्ययता का ध्यान रखा जायेगा तथा बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली एवं शासन के अन्य तद्विषयक आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।
- 3- कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार राक्षग प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य को प्रारम्भ न किये जाये।

21

- 4- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किये जाये।
- 5- एक मुश्त प्रविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य टेकअप किया जाये।
- 6- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।
- 7-आगणन का किसी भी दशा में पुनः परीक्षण नहीं किया जायेगा। कार्य में विलम्ब अथवा पुनरीक्षण की दशा में कार्यदायी संस्था से कार्य लागत का 10 प्रतिशत राशि पेनाल्टी के रूप में कटौती की जा सकेगी।
- 8-भवन हेतु भूकम्प रोधी तकनीक का इस्तेमाल किया जायेगा।
- 9-भवन निर्माण के पूर्व मिट्टी का परीक्षण एवं वाटर हारवेस्टिंग का प्रावधान किया जायेगा।
- 10-प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रत्येक स्थिति में 31 मार्च, 2010 से पूर्व पूर्ण करा लिया जायेगा।
- 11-इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-09 की अनुदान संख्या 07 के लेखाशीर्षक 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय -80-सामान्य -आयोजनागत -800-अन्य भवन -01-केंद्रीय आयोजनागत /केंद्र पुरोनिधानित योजनाएं -0101-12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत राज्य अवस्थापना विकास -24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 12- यह आदेश वित्त विभाग के आशासकीय संख्या-61P/XXVII(5)/08 दिनांक- 18-08-2008 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय
(एन0एर10गपलव्याल)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
 - 2- निजी सचिव, मा0मुख्यमंत्री जी/मा0 राजस्व मंत्री जी।
 - 3- अपर सचिव, वित्त बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
 - 4- अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
 - 5- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
 - 6- निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय।
 - 7- वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
 - 8- वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
 - 9- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था।
 - 10-गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।
2